प्रकाशनार्थ

पटना, 24 सितंबर। इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर (आइजीसी) और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) ने 24 सितंबर 2020 को 'बिहार में लैंगिक अंतराल में कमी के लिए रोडमैप : लैंगिक दायित्वपूर्ण बजट निर्माण' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। पैनल में शामिल लोगों का स्वागत करते हुए आद्री के सदस्य सचिव डॉ. शैबाल गुप्ता ने आयोजन का आरंभ किया। चर्चा का संचालन एमनेस्टी इंटरनेशनल के ग्लोबल इसूज प्रोग्राम की निदेशक यामिनी मिश्रा ने किया। चर्चा के पैनल में बिहार सरकार की प्रधान सचिव सुश्री एन. विजयलक्ष्मी, आइजीसी की प्रिंसिपल इनवेस्टिगेटर सृजना डिक्शन और बिहार सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री एस. सिद्धार्थ शामिल थे।

डा- शैबाल गुप्ता ने कहा कि जेंडर रिस्पांसिव बजटिंग (लैंगिक दायित्वपूर्ण बजट निर्माण) सरकारों द्वारा लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण पर अपनी वचनबद्धताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों के योजना निर्माण आबंटन, कार्यक्रम निर्माण और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण वैश्विक ढांचा है।

बिहार जेंडर रिस्पांसिव बजटिंग के शुरुआती आरंभकर्ताओं में से एक है जिसकी इस संबंध में पहल 2008-09 में शुरू हुई थी। लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण के लिए बिहार का बजट आबंटन 2019-20 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत और राज्य के बजट का 14 प्रतिशत थ। जहां राज्य के समग्र बजट अनुमान में इस अवधि में 3 से 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं जेंडर बजट में बहुत मामूली वृद्धि होती दिखती है। साथ ही, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर जेंडर बजट के बढ़ने का रुझान सकल राज्य घरेलू उत्पाद और लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण संबंधी बजट के बीच सशक्त सकारात्मक रैखिक सहसंबंध के जरिए स्थापित होता है। यह सहसंबंध जेंडर बजट और राज्य की राजकोषीय विशेषता के बीच सशक्त सकारात्मक संबंध को व्यक्त करता है।

जेंडर रिस्पांसिव बजटिंग पर बिहार की नीतिगत वचनबद्धताएं सही दिशा में कदम हैं लेकिन वे उतनी पर्याप्त नहीं दिखती हैं कि उनकी परिणति लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण में निर्गत और परिणाम के स्तर पर हो। पीढ़ीगत लैंगिक असमानता, भेदभाव और हाशिए पर धकेलने की समस्या पर काबू पाने के लिए उनकी रिकॉर्डिंग और निगरानी की जानी चाहिए। शोध में प्रस्तावित है कि लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण पर राज्य की नीतिगत वचनबद्धताओं को जेंडर रिस्पांसिव बजटिंग की सशक्त संचालन संरचना के जरिए साकार किया जाना चाहिए जिसमें मुख्य संस्थागत कर्ता अपनी भूमिकाओं और दायित्व की पहचान करें।

आइजीसी की प्रिंसिपल इनवेस्टिगेटर सुश्री सृजना डिक्शन ने रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस वक्तव्य पर जोर दिया कि ''कोविड-19 पर प्रतिक्रिया की प्रत्येक योजना, और प्रत्येक रिकवरी पैकेज तथा बजट के संसाधन के लिए जरूरी है कि वे इस महामारी के लैंगिक प्रभावों पर कारगर हों' और कहा कि जेंडर रिस्पांसिव बजटिंग के महत्व पर प्रकाश डालना महामारी जैसे समयों में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यूएनडीपी और यूएन वीमन द्वारा हाल ही में शुरू किया गया कोविड-19 ट्रैकर लैंगिक आधार पर अलग किए गए आंकड़े देने में सक्षम है जो रेखांकित करता है कि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बढ़ी है।

सुश्री एन विजयलक्ष्मी ने कहा कि राज्य में जेंडर रिस्पांसिव बजटिंग का परिदृश्य बहुत आरंभिक स्थिति में था और इसको लेकर जागरूकता की कमी थी। तब से आज तक सरकारी अधिकारियों को जागरूक बनाने के लिए हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उनकी सहायता की है और इस मुद्दे पर 22 विभागों में संवेदनीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि संस्थागत विकास जेंडर रिस्पांसिव बजटिंग के लिए एक अवरोधक है और इसीलिए संस्थाओं के विकास की व्यवस्था इसके क्रियान्वयन के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने आंकड़ों, खास कर महिलाओं से संबंधित आंकड़ों और उन आंकड़ों के उपयोग पर भी बल दिया और कहा कि आंकड़े एकत्र करना ही नहीं, उपयोग के लिए उनका विश्लेषण करना भी जरूरी है।

श्री एस सिद्धार्थ ने बताया कि बजट निर्माण के समय हम उसे उस वर्ष के संसाधनों के अनुमान के आधार पर तैयार करते हैं। हमारे सामने एक चुनौती यह आती है कि संसाधनों में कमी दिखती है तो जेंडर रिस्पांसिव बजटिंग का प्रदर्शन कैसे बेहतर हो। यह ऐसी चीज है जिसके बारे में हम अन्वेषण करना चाहेंगे। इसका निर्णय करना बहुत कठिन चुनौती है कि बजट के परिसंपत्ति-निर्माण संबंधी पहलू के लिए संसाधनों का बंटवारा कैसे किया जाय।

आद्री के निदेशक प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने समापन वक्तव्य दिया। उन्होंने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों पर और इस बात पर बल दिया जेंडर रिस्पांसिव बजट निर्माण में उन्हें कैसे शामिल किया जा सकता है।

इस कार्यक्रम के जरिए आद्री और आइजीसी का इरादा बिहार सरकार को ज्ञानमूलक सहयोग देना और अन्य सरकारों के साथ संलग्नता के हमारे अनुभवों को उनके लिए उपलब्ध कराना है। यह वेबिनार आद्री और आइजीसी की सशक्त संयोजन शक्ति और साझेदारी निर्माण क्षमता का एक उदाहरण है।

(अंजनी कुमार वर्मा)